Seventh Five Year Plan are given below:

(i) Motorisation of traditional craft;

(ii) Introduction of improved beach landing craft;

(iii) Group Accident Insurance Scheme and National Welfare Fund for Fishermen covering both inland and marine sectors; and

(iv) Development of Fishing Harbours.

(c) Aproval has been issued for the development of four new fishing harbours, in addition to the second and third stages of development of two existing harbours.

(d) and (e) The proposal for fishing harbour at Nuagarh (Astarang) has already been approved. The proposals for fishing harbours at Gopalpur and Paradip have been circulated for appraisal and for inter-ministerial consultations, on completion of which only the Government could consider the investment decision.

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत देय राशियों का भुगतान

273. **श्री मीर्जा ईर्शादबेग** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले देय राशियों के भुगतान की राज्यवार स्थिति क्या है तथा इन देय राशियों के भुगतान किये जाने के संबंध में अनुमानत: कितना समय लग जाने की संभावना है ;

(ख) फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले खर्च में कुछ और वृद्धि करने के लिए क्या योजनायें है ; और

(ग) क्या सरकार इस योजना को समाप्त करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) बृहत फसल बीमा योजना के अधीन 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान भुगतान किए जाने वाले क्षतिपूर्ति दावों तथा वास्तव में अब तक भुगतान की गई राशि का एक राज्य-वार विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट CXLVIII अनुबंध नं० 3]

(ख) बृहत फसल बीमा योजना के अधीन खर्च में और वृद्धि करने का कोई योजना नहीं है ।

(ग) सरकार इस योजना को समाप्त करने के प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं कर रही है ।

कपास का उत्पादन

274. **श्री मीर्जा ईर्शादबेग** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कपास का राज्यवार उत्पादन कितना हुआ है और इस उत्पादन के आवश्यकता से कितनी मात्रा में अधिक होने की संभावना है ; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने लिए कि किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य मिलें, सरकार की मूल्य नीति क्या होगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) कपास उत्पादन के निश्चित अनुमान राज्यों से अभी देय नहीं है तथापि, कुछ क्षेत्रों में बुआई अभी चल रही है । चालू वर्ष के दौरान वर्षा और जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियां सामान्यत: अनुकूल रही हैं तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आलोच्य वर्ष के

लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिए जाने की सम्भावना है ।

(ख) जैसा कि अन्य कृषि जिन्सों के मामले में है, कपास के सम्बन्ध में सरकार की मूल्य निर्धारण नीति कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने की है । कपास उत्पादकों की न्यूनतम समर्थन मूल्यों की गारन्टी देने के लिए सरकार जब कभी यह देखती है कि बाजार मूल्य सरकार द्वारा घोषित समर्थन स्तर से कम हो रहे हैं तो वह भारतीय कपास निगम के जरिए कच्ची कपास की वसूली करने का प्रबंध करती है ।

राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत समाचारों का दूरदर्शन पर प्रसारण

275. **श्री मीर्जा ईर्शाद बेग** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदशन द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत भारत की राजभाषा और अंग्रजी में प्रसारित किये जाने वाले समाचारों में एकरूपता न बरते जाने के क्या कारण हैं, विदेशों की अधिकतर खबरें दूरदर्शन के अंग्रेजी समाचारों में ही प्रसारित किये जाने के क्या कारण हैं और राजभाषा के साथ किये जा रहे इस अन्याय को कब तक समाप्त किये जाने की संभावना है ; और

(ख) उक्त भाषागत असमानता को कब तक समाप्त कर दिये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) (क) और (ख) अंग्रेजी और हिन्दी समाचारों की विषय-वस्तु प्रायः एक जैसी होती है । किसी समाचार के महत्व तथा व्यापक लोक हित को देखते हुए उस समाचार को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों बुलेटिनों में दिया जाता है । समाचारों में किसी भी समाचार को शामिल करने के मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार समाचारों के लिए उसकी उपयोगिता का होना है। दो भाषाओं के समाचार बुलेटिनों में एकरूपता रखना संभव नहीं है । हिन्दी समाचार तैयार करते समय पर्याप्त ध्यान रखा जाता है ताकि वे भी अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों के क्रम के अनुरूप हों ।

Vacant posts in Vocational Rehabilitation Centres in Jaipur and Bhubaneshwar

276. SHRI BHAGATRAM MANHAR: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are some vacancies of Vocational Instructors (Cutting & Tailoring) which have been lying vacant in Vocational Rehabilitation Centres in Jaipur & Bhubaneshwar since long;

(b) whether it is also a fact that the concerned authorities of both VRC's had advertised these vacant posts in the Employment News long back and applications received from various Exchanges had been lying pending with no action; and

(c) what are the reasons for not considering eligible candidates till now & what is the latest fate of this case and by which specific date the selection of the eligible candidates is likely to be completed?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY): (a) to (c) There is no vacant post of Vocational Instructor (Cutting & Tailoring) at Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jaipur. Since a temporary vacancy of Vocational Instructor (Cutting & Tailoring) arose at this Centre due to appointment of the incumbent in another organisation, applications from open market were invited. However, the incumbent sought reversion to his post and joined at Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jaipur.